

मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

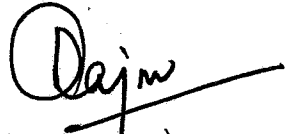
भोपाल, दिनांक 24/04/2019

क्रमांक एफ 12-08/2019/32-3-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना क्रमांक जीएसआर 338 (ई) दिनांक 23/03/2016 द्वारा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 प्रकाशित किये गये हैं जो सम्पूर्ण भारत में दिनांक 01/10/2016 से प्रभावशील हैं। नियमों में इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल उपकरणों के उपयोग पश्चात् प्राधिकृत संस्थाओं के माध्यम से अपवहन (Disposal) किये जाने का प्रावधान है।

2/ माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली प्रकरण क्रमांक 512/2018 (शैलेश सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 12/02/2019 के परिप्रेक्ष्य में उक्त नियमों के प्रावधानों के प्रदेश में पालन की समीक्षा हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन -अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, मध्य प्रदेश शासन
अथवा उनके प्रतिनिधि -सदस्य
3. प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश शासन
अथवा उनके प्रतिनिधि -सदस्य
4. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन
अथवा उनके प्रतिनिधि -सदस्य
5. क्षेत्रीय संचालक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल -सदस्य
6. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल - संयोजक

3/ वर्ष में कम से कम दो बार बैठक का आयोजन किया जावेगा। बैठक में आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ/अन्य अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।


(अनुपम राजन)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
dc

पृ.कमांक एफ 12-08 /2019/32-3

भोपाल,दिनांक 24/04/2019

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
4. क्षेत्रीय संचालक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहकार भवन, नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
6. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय ।
7. विधि अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
8. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय की ओर टीप कमांक 2836/सीएस/मॉनिट/2019, दिनांक 18/4/2019 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया उक्त मॉनिट प्रकरण को लंबित प्रकरणों की सूची से विलोपित करने का कष्ट करें ।



प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

dz